

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 37/2019

**अपीलांट्स-**

1. उदयसिंह पुत्र धूड़सिंह
  2. चैनसिंह पुत्र धूड़सिंह
- जाति राजपूत निवासी नौसर तहसील  
बायतु जिला बाड़मेर

**बनाम**

**रेस्पोंडेंट्स-**

1. राज0 सरकार जरिये नायब  
तहसीलदार बाड़मेर
  2. गजेसिंह पुत्र भीखसिंह
  3. रतनसिंह पुत्र भीखसिंह
  4. बाबूसिंह पुत्र गणपतसिंह
  5. शेरसिंह पुत्र गणपतसिंह
- जाति राजपूत निवासी नौसर  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 104 जो दिनांक 04.12.1978 जो नायब  
तहसीलदार बाड़मेर द्वारा रेस्पोंडेंट सं. 2से5 के पूर्वज भीखसिंह के पक्ष  
में स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोंडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. अवशेष रेस्पोंडेंट बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

**निर्णय**

दिनांक : 15.03.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम के तहत ग्राम गिरली कितपाला के नामान्तरकरण सं. 104 पर  
नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 04.12.1978  
के विरुद्ध दिनांक 22.07.2019 को प्रस्तुत की गई हैं।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गिरली कितपाला के  
खसरा नम्बर 48, 49, 28 रकबा क्रमशः 22-14, 41-01, 06-09 बीघा में



जिला कलक्टर  
बाड़मेर

धूड़सिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत सा0 नोसर खातेदार के नाम से दर्ज थी। हल्का पटवारी डंडाली द्वारा दिनांक 04.12.1978 के अभियान के दौरान बयान लेने के बाद भीखसिंह पुत्र विशनसिंह 1/2 नाम दर्ज करने का आदेश दिये जाने के अनुसरण में नामान्तरकरण सं. 104 धूड़सिंह पुत्र विशनसिंह 1/2, भीखसिंह पुत्र विशनसिंह 1/2 राजपूत सा0 नोसर खातेदार के नाम दायर कर नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 04.12.1978 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट्स ने नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट्स ने इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं तथा यह नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य हैं। रेस्पोंडेंट्स के पूर्वज भीखसिंह ने अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार बाड़मेर को प्रभावित कर दिनांक 04.12.1978 को अभियान के दौरान अपीलांट्स के पिता स्व0 धूड़सिंह की खातेदारी भूमि में रेस्पोंडेंट के पूर्वज भीखसिंह ने 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाकर विधि विरुद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। ग्राम गिरली कितपाल के खसरा नम्बर 48, 49 व 28 की कुल 70-04 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त अपीलांट्स के पिता धूड़सिंह के नाम दर्ज हुई थी तथा उनके पश्चात उक्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा-काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोंडेंट सं. 2से5 के पिता भीखसिंह को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से स्वीकृत किया है जबकि नायब तहसीलदार को किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि में से किसी को किसी भाग का खातेदारी अधिकार प्रदान




किल्ला कलक्टर  
बाड़मेर

करने एवं खातेदारी अधिकार समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अधिकार विहित होने से प्रारम्भ से ही शुन्य है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या निर्णय के अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 104 के द्वारा रेस्पोंडेंट सं. 2से5 के पिता भीखसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह अधिकार से रहित एवं विधि के प्रतिकूल है। विवादित भूमि पर कभी भी भीखसिंह एवं उनके उत्तराधिकारियों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अपीलाट्स ने माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में तहसील सिणधरी जाकर अपने खेतों का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कराने हेतु जमाबन्दी की नकलें मांगी तो हल्का पटवारी डंडाली ने बताया कि विवादित खेतों में 1/2 हिस्सा भीखसिंह के वारीसान का है तथा अपीलाट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण के बारे में जानकारी हुई। इस पर अपीलाट्स ने बाड़मेर आकर राजस्व अभिलेख एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 04.07.2019 को मांगी जो प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से शुन्य होने से इसे चुनौति देने हेतु कोई मयाद निर्धारित नहीं है फिर भी अपील को प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है उसे पृथक से आवेदन पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलाट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 104 पर पारित किया गया स्वीकृति आदेश दिनांक 04.12.1978 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोंडेंट सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब यह प्रकट किया कि अपीलाट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 104 स्वीकृति दिनांक 04.12.1978 की जानकारी प्रारम्भ से ही थी तथा उक्त नामान्तरकरण राजस्व अभियान के दौरान अपीलाट्स के पिता की सहमति बयान से स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये गये हैं। अपीलाट्स को राजस्व अभिलेख में रेस्पोंडेंट्स सं. 2से5 के पिता एवं उनके बाद रेस्पोंडेंट्स का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने की जानकारी थी इसके बावजूद अपीलाट्स ने जानबूझकर उसे चुनौति नहीं दी है। अपीलाट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब का कोई संतुष्टिपकरण कारण प्रकट नहीं किया गया है जबकि विधि की मंशा अनुसार पक्षकार को विलम्ब के एक-एक दिन का कारण प्रकट करना



  
जिला न्यायालय  
बाड़मेर


आवश्यक हैं। इसके अलावा अपीलांट्स को जब अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी होने एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज होने के बावजूद इनके द्वारा जानबूझकर इतनी लम्बी समयावधि तक अपने हक-हकूकों के लिये उदासीन रहकर चाराजोही नहीं करने पर अब उन्हें असाधारण विलम्ब के पश्चात इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलांट्स द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति के करीब 42 वर्ष के असाधारण विलम्ब के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है जो किसी भी दशा में श्रवण योग्य नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत होने की जानकारी के जो तथ्य बताये गये हैं वह कतई विश्वास काबिल नहीं होकर सरासर मनगढ़त हैं। अपील की सुनवाई से पूर्व मयाद के बिन्दु पर निश्चय हेतु अपीलांट्स की ओर से एक-एक दिन के विलम्ब का टोस एवं तथ्यपरक कारण प्रकट करना माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट्स की यह अपील मयाद के बिन्दु पर ही कतई स्वीकार योग्य नहीं है, जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 104 दिनांक 04.12.1978 के अभियान के दौरान बयान लेने के बाद दिये गये आदेश की पालना में दायर किया गया है जिसका उल्लेख कॉलम सं. 14 में स्पष्ट रूप से किया गया है। उक्त कॉलम सं. 14 में हल्का पटवारी द्वारा अंकित किया गया है कि-

“आज दिनांक 04.12.1978 के अभियान के दौरान बयान लेने के बाद भीखसिंह पुत्र विशनसिंह 1/2 नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया।”


इस प्रकार स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि धूड़सिंह पुत्र विशनसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिसके साथ हिस्सा 1/2 में भीखसिंह पुत्र विशनसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है तथा इसके लिये किसी सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं था और न ही कॉलम सं. 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि अभियान के दौरान किसके द्वारा बयान लिये गये एवं आदेश दिया, जिसकी पालना में यह नामान्तरकरण दायर किया गया है। नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस तथ्य की जांच किये बिना इसे स्वीकृत कर दिया गया। अब जहां तक इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत इस अपील में



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

मयाद का प्रश्न है तो अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार को अनदेखा करते हुए अवैध रूप से पारित आदेश प्रारम्भ से शून्य की परिभाषा में आता है जिसके लिये मयाद बाधित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर आरबीजे (22) 2015 पेज 482 प्रस्तुत किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया है कि विलम्ब के समुचित कारण को सारभूत न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से उदारतापूर्ण रूप में लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार एआईआर 2013 पेज 3060 के उद्धरण प्रस्तुत किये गये, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जहां क्षेत्राधिकार के संबंध में जहां मामला आरम्भ का बिन्दु है तो उसे किसी भी समय उठाया जा सकता है तथा डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर लागू नहीं होगी। इसी प्रकार आरआरडी 1992 पेज 173 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्धारित किया है कि क्षेत्राधिकार विहित आदेश के विरुद्ध अपील के लिये मयाद लागू नहीं होगी। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा आरएलडब्ल्यू 1997 (2) राज. पेज 968 की निर्णय नजीर प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि किसी न्यायालय द्वारा विवाद के निराकरण हेतु मामला ले लिया जाता है जिसके लिये उसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो उस मामले में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री शून्य है तथा ऐसी डिक्री की वैधता को किसी भी समय, अपील में अथवा किसी निष्पादन की कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है। इसके विरुद्ध अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2007(2) पेज 788, आरआरटी 2009(1) पेज 488, आरआरटी 2007(2) पेज 939 व आरआरटी 2009(1) पेज 432 के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए विलम्ब के उपशमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित मत पर बल देते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण को समुचित नहीं होना मानते हुए मयाद के बिन्दु पर खारिज करने का अभिकथन किया है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त निर्णय नजीरों में हस्तगत प्रकरण के समान रूप में क्षेत्राधिकार का बिन्दु विवेचित एवं निष्कर्षित नहीं किया गया है। हस्तगत अपील में अभिलेखीय तौर पर साबित है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर खातेदारी दिये जाने का पारित किया है जो अवैध आदेश है तथा नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व पक्षकारान को



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का भी कोई साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स का यह कथन कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, मानने योग्य नहीं है एवं अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर अनुसार डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर क्षेत्राधिकार विहित आदेश के विरुद्ध लागू नहीं होगी। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण अवैध एवं प्रारम्भ से शुन्य आदेश की परिधी में आने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा गिरली कितपाला के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 104 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता है उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज अद्यतन किये जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( विश्राम मीणा )  
जिला कलेक्टर बाड़मेर  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर